Linkage of cities and towns in Orissa with National Highways

*30. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will, the Minister of. SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) the names of the cities and towns in Orissa connected with different National Highways:

(b) whether Government of Orissa has requested the Central Government to provide link roads and also develop the already existing State roads between those National Highways;

(c) if so, the details of the proposals received by the Ministry in that regard; and

(d) the steps taken to consider those proposals?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS AND MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRI M. THAMBI DURAI): (a) There are two nos. of cities and 26 nos. of towns as per the list enclosed in the statement *(see* below), connected with different National Highways in Orissa State.

(b) No, Sir.

(c) and (d) Do not arise.

Statement

Name and the number of cities and towns in Orissa connected with different National Highways

S. No.	Name of town	Connecting N.H.s.
" 1.	Berathampur	5
2.	Chhatarapur	5
3.	Ganjam	5
4.	Rambha	5
5.	Balugaon	5
6.	Khurda	5
7.	Bhubaneswar (City)	5
8.	Cuttuck (City)	5
9.	Bhadrak	5
10.	Balasore	5
11.	Soro	5
12.	Baripada	5
13.	Kendrapara	5A
14.	Paradip	5A
15.	Keonjihar	6
16.	Deograh	6
.17.	Sambalpur	6
18.	Burha	6
19.	Bargarh	6
20.	Talcher	23
21.	Rourkela	23
22.	Biramitrapur	23
23.	Choudwar	42
24.	Dhenkanal	42
25.	Angul	42
26.	Koraput	43
27.	Sunabeda	43
28.	Jeypore	43

Agenda for the Revival of Economy

*31. SHRI SITARAM KESRI:
SHRI BANGARU LAXMAN:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state;

(a) whether the Prime Minister has recently announced economic package to boost economy; and

(b) if so, the details thereof and the steps so far taken in pursuance thereof?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YA.SHWANT SINHA): (a) and (b) While addressing 71st Annual session of Fedration of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) on October 24, 1998, the Prime Minister announced a number of initiatives to boost the economy. Initiatives announced by the Prime Minister concern development of the capital market, disinvestment, opening up of the insurance sector to the Indian Private sector, investors Protection and measures to restore their confidence.

Other proposals for the development infrastructure, include building up of 7,000 KM road corridor connecting Kashmir to Kanyakumari and Silichar to Saurashtra, construction of five world class international airports, a new Internet policy and formulation of new telecom policy to provide state-of-the-art nation-wide telecommunication network and speed up rural telephone services.

बैंकों /सहकारी समितियों द्वारा कृषि ऋण

32.**श्रीमती सरोज दुबे**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षो के दौरान,वर्ष –वार तथा 1998 में आज तक वाणिज्यिक बैंकों,क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी समितियों द्वारा राज्य-वार कितना-किना कृषि ऋण दिया गया ;और

(ख) किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि ऋण की राशि बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं /उठाये जाने का विचार हैं ?

वित्त मंत्रालय बैंकिग,राजस्व तथा बीमा में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम.आर.जनार्दनन): (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि एंव ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा कृषि एंव संबंद्व क्षेत्रों के तहत वितरित बुनियादी स्तर के कुल ऋणों में वर्ष 1995-96 में 22032 करोड़ रू.की वृद्वि हुई तथा वर्ष 1996-97 के दौरान इन ऋण में और वृद्वि हुई एंव ये ऋण 26411 करोड़ रूपए के हो गए जिससे वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के दौरान क्रमश: 18% और 20% की वार्षिक वृद्वि दर्ज की गई । वर्ष 1997-98 के दौरान बुनियादी स्तर के ऋणों के 30976 करोड़ रूपए (अनन्तिम) तक पहुंचने का अनुमान है । वर्ष 1995-96,1996-97 तथा 1997-98 (अनन्तिम) के दौरान कृषि के एजेंसी –वार ब्यौरे निम्नलिखित है :-

वर्ष	वाणिज्यिक बैंक	सहकारी बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	कुल
1995-96	10,172	10,479	1,381	22,032
1996	12,783	11,944	1,684	26,411
1997-98 (अनन्तिम)	14,462	14,339	2,175	30,976
वर्ष	वाणिज्यिक बैंक	सहकारी बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	कुल

राज्य-वार ब्यौरे संलग्र विवरण में दिए गए हैं (**नीचे देखिए**)

भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड ने कृषि के लिए ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए कुछ उपाय किए हैं,जिनमें,अन्य बातों के साथ-साथ,सहकारी बैंकों को सुदृढ़ बनाने के लिए उपाय,क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुन: अर्थक्षम बनाना,नाबार्ड की शेयर पूंजी तथा क्षमता बढ़ाना,ऋण सीमाओं में वृद्वि एंव स्व-सहायता समूह संयोजना बढ़ाना शामिल है । भारतीय रिजर्व बैंक के भूतपूर्व उपगर्वनर श्री आर.वी.गुप्ता की एक सदस्यीय समिति ने संवितरण प्रणाली और साथ ही कृषि ऋण की प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए उपाय सुझाए थे । आर.वी.गुप्ता समिति द्वारा की गई अधिकांश सिफारिशें स्वीकार कर ली गई है,जिनमें ऋण आवेदन-पत्रों से संबंधित प्रक्रियाओं का सरलीकरण शाखा प्रबंधकों को शक्तियों का प्रतयायोजन कृषि कार्य करने वाले किसानों के लिए संमिश्र ऋण सीमा शुरू करना,बचत संघटकों सहित नए ऋण उत्पाद शुरू करना,ऋणों का नकद संवितरण,10,000/- रूपए से अधिक के कृषि ऋणों हेतु मार्जिन प्रतिभूति अपेक्षाओं से संबंधित मामलों में बैंकों का स्वनिर्णय तथा अनिवार्य अपेक्षा के रूप में "अदेयता प्रमाण-पत्र" से छूट देना शामिल है ।